that the Central Government may give the necessary approval early giving due regard to the sentiments and aspirations of the people of Maharashtra. It would have been better if the Government had announced its decision before May 1, the Maharashtra Day, but this not having been done, I would request the Central Government to give its approval at an early date, for there is a lot of agitation among the people of Maharashtra on the question. It is a question of national self-respect.

REFERENCE TO THE SHORTAGE OF POWER IN WESTERN UTTAR PRADESH CAUSING HARDSHIP TO FARMERS

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय उपसभापति महोदय, किसानों का गेहूं खलिहानों में कटा पड़ा है । उसके थ्रेसिंग के लिए बिजली की आवश्यकता है । आप जानते है कि पिछले कई वर्षों से उसका गेहूं प्रति वर्ष वर्षा के कारण खलिहानों में पड़ा खराब होता रहा है । उसका अनाज भी खराब हो जाता है और भूसा भी खराब हो जाता है । उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह घोषणा की है कि किसानों को 10 घंटे बिजली मिलेगी । लेकिन दुर्भाग्यवश किसानों को दो घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है और इससे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि जो थ्रेसर ओनर्स हैं, जो पूंजीपति व्यक्ति हैं उनको चौबीसों घंटे बिजली मिलती [illegible] किन किसानों के लिए बिजली उपलब्ध नहीं है । ऐसी स्थिति में किसान न तो अपने गेहूं को थ्रेश करके उठा सकता है और न कोई और काम कर सकता है । अगर उसको बिजली मिले तो वह आबपाशी करके गेहूं के खेत जो इस समय खाली पड़े हुए हैं उनमें नया ईख बोयेगा । श्रीमन्, आप भली प्रकार से जानते हैं कि पश्चिमी उत्तरप्रदेश की अर्थ व्यवस्था मूलतः गन्ने पर मुनहसिर करती है । अगर गन्ना समय पर नहीं बोया जा सका और कुछ दिनों में गन्ने को पानी नहीं मिला तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो जायेगा । गन्ने को पहले पानी की आवश्यकता होती है । अगर उसको पहला पानी नहीं मिला तो गन्ना मर जाएगा । यह जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है और किसानों के लिए बिजली की जो कमी हो गई है उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान खिचना चाहता हूं । मैं आप के माध्यम से शासन से प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस तरफ तुरंत ध्यान दे । श्रीमन्, आप भी किसान हैं और आप की किसानों के साथ सदैव सहानुभूति रही है और आप उनके संबंध में चिंता रखते हैं, इसलिए आप हमारी इस प्रार्थना को सरकार तक पहुचाने की कृपा करें जिससे किसानों को बिजली उपलब्ध हो सके । दूसरी बात मैं यह और कहना चाहता हूं कि किसानों का दुर्भाग्य है कि उनको डीजल भी उपलब्ध नहीं हो रहा है । इतने बड़े स्टेट में डीजल की बड़ी स्केयरसिटी है और स्थिति यह हो गई है कि किसानों को डीजल ब्लैकमार्किट में लेना पड़ रहा है और वह भी अडलट्रेटड मिल रहा है, उसमें मिलावट है । डीजल नहीं मिल रहा है और नहीं सरकार बिजली दे पा रही है तो फिर किस प्रकार से किसान कृषि ओपरेशन का संचालन कर सकता है ? वह न तो अपने कृषि कार्य कर सकता है और न ही खेतों [illegible] है । बिजली न मिलने के कारण [illegible] वह सिंचाई कर सकता है, न थ्रेसिंग कर सकता है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस परिस्थिति को आप सरकार तक पहुंचा दें । चूंकि आप एक किसान हैं, इसलिए मैं

आशा करता हूं कि आप हमारी इन भावनाओं को मंत्री महोदय तक पहुंचाने की कृपा करेंगे ।

REFERENCE TO THE REPORTED SHORTAGE OF VANASPATI GHEE IN DELHI, U.P. AND HARYANA

श्री शांति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, राजधानी दिल्ली, हरियाणा में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देश के अन्य भागों के बारे में मुझे मालूम नहीं है-इस समय वनस्पति तेल की बड़ी कमी हो गई है । यह बात आपने अखबारों में भी पढ़ी होगी । अभी श्री विरेन्द्र वर्मा जी ने बिजली की कमी की बात बताई । माननीय वर्मा जी ने कहा कि बिजली का अकाल है । डीजल नदारद है और सबसे बड़ी चीज जो हर घर में इस्तमाल होती है बड़े घरों में तो देशी घी इस्तमाल होता है मगर साधारण लोगों के घरों में कुकिंग मीडियम वेजीटेबल घी है वह खुले बाजार में बिल्कुल नदारद है । मैं यह अखबारों की बात नहीं कह रहा हूं बल्कि इसका स्वयं भुक्तभोगी हूं । मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी यही स्थिति है । वेजिटेबल घी निर्माताओं का दावा यह है कि इस साल में उत्पादन बढ़ा है । आज घी की और भी ज्यादा आवश्यकता है, मैं आप की सेवा में यह निवेदन कर दूं कि आजकल शादियों का मौसम है । मुझे आपके यहां का मालूम नहीं है लेकिन हमारे यहां के छोटे-छोटे गांवों में भी आठ-आठ शादियां हैं । मैं आप से गुजारिश करूंगा कि उनके पास कुकिंग का कोई दूसरा मीडियम नहीं है, तेल सरसों का भी बहुत मंहगा है और लोग धक्के खाते फिर रह हैं मगर घी ब्लैक मार्किट में बिक रहा है । आपने मुझे यह स्पेशल मेंशन करने की इजाजत दी है इसके लिए मैं आप का बहुत आभारी हूं । मैं आप के माध्यम से और माननीय सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हर चीज का अकाल पैदा मत करो । भले आदमियों बिजली नहीं है, भले आदमी डीजल नहीं है और उसके बाद खाने का एकमात्र मीडियम है, वह बहुत अच्छा घी तो नहीं है, फिर भी काम आता है, उसे सरकार जनता को उपलब्ध करे । यह सरकार जनता के आशीर्वाद से ही बनी हुई है इसलिए जनता की भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए । धन्यवाद ।

REFERENCE TO THE DIFFICULTIES REPORTEDLY BEING FACED BY TEACHERS AND OTHER STAFF OF THE SAINIK SCHOOLS

श्री सत्यपाल मलिक (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं जो मामला उठाना चाहता हूं वह देश के जो सैनिक स्कूल हैं उनमें जो पढ़ाने का काम अध्यापक करते हैं और जो दूसरे कर्मचारियों की सेवा शर्तें हैं उन से सम्बन्धित है । 1961 में सैनिक स्कूल शुरू किए गए थे । इनकी संख्या आरंभ में 12 थी । इनकी स्थापना करना जरूरी भी थी । इन स्कूलों के करीब 30 प्रतिशत विद्यार्थी फौज में काम पा गये हैं और बाकी लोग भी जिन्दगी की बेहतर जगहों पर पहुंचे हैं । इन स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइयटी नाम की एक आटोनोमस संस्था है वह चलाती है जिसके हैड होते हैं डिफेंस मिनिस्टर-और इनके बोर्ड के डाइरेक्टर जिस सूबे में स्कूल होता है उस सूबे के मुख्य मंत्री या शिक्षा मंत्री होते हैं । इस समय इन स्कूलों की संख्या 18 है । इन स्कूलों के प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार फौज के अफसर होते हैं और वे इन स्कूलों में आन डेपूटेशन होते हैं लेकिन उनके नीचे के तमाम कर्मचारी सिविलियन होते हैं । आज यह स्थिति है कि जो कर्मचारी या अध्यापक वहां कार्यरत हैं उनकी सेवा की कोई सुरक्षा नहीं है । वहां ज